सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_Sanjay YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 8 ● अंक: 77 ● पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, गुरुवार, 21 अप्रैल, 2022
मूल्य ₹ 3/-

शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउन्ट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का।
-डा. एपीजे अब्दुल कलाम

बुलडोजर पर देशव्यापी स्टे नहीं... 8 | अब प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को... 3 | यूपी बोर्ड: अब नए पैटर्न से होंगी... 7

अक्षय कुमार ने मांगी माफी मगर देश में कब लगेगा पान मसाले पर प्रतिबंध!

देश में धड़ल्ले से बिक रहा पान मसाला, अफसरों से मिलीभगत कर सरकार को कंपनियां लगा रहीं चूना

नशे के विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बाद गुटखे की जगह इलायची का कर रहीं विज्ञापन

» पान मसाला बेचने के लिए सुपर स्टार अभिनेताओं से कराये जा रहे करोड़ों के विज्ञापन

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। देश में एक नयी सोच पैदा हुई है और वह है अपने नायकों को कठघरे में खड़ा करने की। अक्षय कुमार के करोड़ों लोग दीवाने हैं और उनमें अपना नायक तलाशते हैं। अक्षय कुमार को विमल पान मसाला कंपनी का एड करते देख लोग निराश हुए और सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना की, जिसके बाद अक्षय ने इस एड के लिये माफी मांगी पर बड़ा सवाल यह है कि देश में लाखों लोगों की मौत की जिम्मेदार इन पान मसाला कंपनियों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगता। **4PM** के संपादक संजय शर्मा ने पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने के लिये इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की थी जो अभी लंबित है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने नशे के विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। शराब और पान मसाला की कंपनियों का धंधा विज्ञापन पर ही चलता है। इस रोक के बाद इन कंपनियों ने नया रास्ता निकाला। रजनीगंधा, विमल पान मसाला और शुद्ध प्लस कंपनियों ने पान मसाला के गुटखे की जगह इलायची का विज्ञापन शुरू कर दिया। विमल कंपनी ने तो प्रचार के लिये सारे रिकार्ड ही तोड़ डाले। बड़े-बड़े फिल्मी सितारों को एक मूवी के लिये जितने पैसे मिलते हैं उतने पैसे अकेले एक एड के मिलने लगे। लिहाजा अजय देवगन और शाहरुख खान मुंह में गुटखा डालते हुए विमल इलायची का विज्ञापन करते नजर आने लगे। लोग तब हैरान हुए जब पिछले हफ्ते इसी एड में अक्षय कुमार भी नजर आने लगे। अक्षय कुमार सामाजिक कार्यों , स्वच्छता और हेल्थ के मुद्दे को लेकर लोगों को जागरूकता करते रहते हैं। इस एड के बाद देश भर में उनकी आलोचना शुरू हो गयी। हंगामे के बाद कल देर रात अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए अपने प्रशंसकों से इस एड के लिये माफी मांगी और कहा, इस एड का सारा पैसा वे दान कर देंगे। अक्षय कुमार ने लिखा, आई एम सॉरी। मैं आप सभी शुभचिंतकों और फैंस से माफी मांगता हूं। पिछले कुछ दिनों में आपकी प्रतिक्रियाओं ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। हालांकि, मैंने कभी तंबाकू को प्रमोट नहीं किया और न ही करूंगा। अक्षय की इस माफी के बाद बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि आखिर हर साल लाखों लोगों की मौत के जिम्मेदार पान मसाले को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाता। यह स्थिति तब है जब देश में हर घंटे पांच लोगों की मुंह के कैंसर से मौत हो रही है।

जीएसटी की चोरी करती हैं कंपनियां

यूपी में भी पान मसाला कंपनियां जीएसटी की बड़े पैमाने पर चोरी करती हैं। मूल फैक्ट्री के अलावा ये दूर गांव में चुपचाप छोटे-छोटे कारखाने लगा लेती हैं और यहां पर बनने वाले माल की टैक्स चोरी का आधा पैसा सरकारी अफसरों को घूस में दे देती हैं।

देश में हर घंटे पांच लोगों की मुंह के कैंसर से हो रही है मौत

ओरल कैंसर पर ढाई दशकों से रिसर्च कर रहे अहमदाबाद के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. भरत अग्रावत के मुताबिक मुंह के कैंसर की बीमारी में ओरल सबम्युकस फाइब्रोसिस पूर्व स्थिति है। प्रतिवर्ष भारत में इसके 77 हजार मामले सामने आते हैं। इस बीमारी का विस्तार इतना भयावह है कि प्रति घंटे देश में करीब पांच लोगों की मुंह के कैंसर से मौत हो रही है। ओरल कैंसर दुनिया में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है लेकिन सिर्फ भारत में ही एक तिहाई से अधिक मामले पाए जाते हैं। गुटखा और तंबाकू मुंह के कैंसर का बड़ा कारण हैं।

टैक्स चोरी के अलावा गुंडागर्दी में भी नाम आया था शुद्ध प्लस का

शुद्ध प्लस पान मसाला कंपनी का नाम न केवल टैक्स चोरी बल्कि गुंडागर्दी करने में भी आ चुका है। कानपुर में अपने बाउंसर के सहारे शुद्ध प्लस पान मसाला कंपनी के निदेशक शरद खेमका ने अपनी फरारी कार से बीच चौराहे पर जमकर स्टंट किया था। इस दौरान पुलिस तमाशबीन बनी थी। इस मामले में देर से एफआईआर दर्ज करने की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी की गई थी। तब सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने इस मामले में सीएम योगी को पत्र लिखकर ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों और शरद खेमका के अन्य सहयोगियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की थी।

4PM के संपादक संजय शर्मा ने हाईकोर्ट में दायर की थी जनहित याचिका

वर्ष 2020 में कोरोना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले 25 मार्च को पान मसाले पर प्रतिबंध लगाया लेकिन उसे अचानक 6 मई को वापस ले लिया था। इस पर **4PM** के संपादक संजय शर्मा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर पान मसाले पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। **4PM** के संपादक संजय शर्मा ने याचिका में कहा था कि पान मसाला के उत्पादन, वितरण और बिक्री की अनुमति देने वाली सरकार के 6 मई के आदेश केंद्र सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रोटोकॉल की भावना के खिलाफ हैं। याचिकाकर्ता ने कहा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान सहित तंबाकू के उपयोग और थूकने पर रोक लगाने के लिए कहा है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना कोरोना वायरस के प्रसार को बढ़ा सकता है। याचिका में कहा गया कि 25 मार्च, 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने पान मसाला के इस्तेमाल और सार्वजनिक थूकने पर चिंता जताते हुए पान मसाला के निर्माण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था जिससे महामारी फैल सकती है। याचिका में हैरत जताते हुए कहा गया था कि कोरोना के बढ़ते प्रसार के बावजूद पान मसाला पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के आयुक्त, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने 6 मई के आदेश से प्रतिबंध को वापस ले लिया है। याचिकाकर्ता और **4PM** के संपादक संजय शर्मा ने सवाल उठाया था कि आयुक्त, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि पान मसाला से कोरोना का प्रसार नहीं बढ़ेगा। यह स्थिति डरावनी है लिहाजा यह आदेश राज्य के नागरिकों के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करता है। यही नहीं इस आदेश को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 का उल्लंघन कर पारित किया गया है, जो आयुक्त को सार्वजनिक हित में कार्य करने के लिए कहता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 75,000 व्यक्ति मुंह के कैंसर की खतरनाक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसका मुख्य कारण तंबाकू चबाना और गुटखा और पान मसाला का उपयोग करना है। फिलहाल यह मामला कोर्ट में लंबित है।

रजनीगंधा ने कहा था, दस करोड़ दिये पीएम फंड में, बैन न करें पान मसाला

दूसरी लहर के दौरान वर्ष 2020 में पान मसाला को बैन करने की मांग वाली एक जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गयी थी। पान मसाला बंद न हो इसके लिए रजनीगंधा कंपनी ने हैरान करने वाला तथ्य कोर्ट में रखा था। कंपनी ने कहा था कि लोग रजनीगंधा को माउथ फ्रेशनर की तरह चबाते है और इसमें तंबाकू नहीं होती। उन्होने शपथ पत्र देकर कहा कि उन्होने कोरोना काल में पीएम केयर फंड में दस करोड़ दिये है और अन्य कोरोना वॉरियर एवं कोरोना से लड़ाई को भी दस करोड़ दिये है। इन सब बातो के मददेनजर पान मसाला को प्रतिबंधित न किया जाय। सवाल यह है कि क्या पीएम फंड में दान देने भर से पान मसाला कंपनियों को लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने की छूट दी जा सकती है?

सौ दिनों में हर हाल में चालू हो जाएं सभी ग्राम सचिवालय : सीएम योगी

» एक ही छत के नीचे ग्रामीणों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिए निर्देश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। एक ही छत के नीचे ग्रामीणों को सभी सरकारी विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराने की अपनी मंशा को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 दिनों में सभी ग्राम सचिवालयों को पूरी तरह चालू करने और उनमें ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पंचायत सचिवों की क्लस्टर के अनुसार तैनाती करने के लिए कहा है। छह महीने के भीतर 1.5 लाख इज्जत घरों का निर्माण कराने का निर्देश भी दिया है।

ग्राम्य विकास सेक्टर से जुड़े विभागों की कार्ययोजनाओं के प्रस्तुतीकरण के दौरान उन्होंने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिया कि 100 दिनों में ग्राम सचिवालयों में जन सेवा केंद्र (सीएससी) की सह-स्थापना के बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएं। पंचायत भवनों में सीएससी के 750 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों का चयन करने के साथ धनराशि जारी की जाए। इज्जत घरों के निर्माण पर जोर देने के साथ ओडीएफ प्लस ग्राम

योजना के अनुरूप 5000 गांवों में काम शुरू करने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री ने हर ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर का विकास करने और प्रत्येक जिले में कम से कम दो माडल ग्राम पंचायतों को सभी मूलभूत सुविधाओं व विकास कार्यों से लैस करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हर गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र जरूर हो। सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव की अच्छी व्यवस्था हो। गांवों में ठोस कचरे को कंपोस्ट के रूप में प्रसंस्कृत करने के प्रयास हों। गांवों में ड्रेनेज प्रणाली को बेहतर करने की जरूरत है। सीएम योगी ने कहा बरसात के पहले नालों को डी-सिल्ट कर दिया जाए। गांवों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री ने बलिया में निर्मित क्षेत्रीय पंचायत रिसोर्स सेंटर को चालू करने के लिए कहा। नवाचार व उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म का इस्तेमाल करने और पंचायत प्रतिनिधियों को एक्सपोजर विजिट कराने पर भी जोर दिया।

रिटायर राज्य कर्मियों के लिए ई-पेंशन पोर्टल के जरिए नई व्यवस्था लागू

उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को अब सेवानिवृत्त होने के बाद भुगतान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों का पेंशन पेमेंट आर्डर जारी होने के बाद उनकी ग्रेच्युटी तथा राशिकरण का भुगतान सेवानिवृत्ति तिथि से अगले तीन कार्यदिवसों में कर दिया जाएगा। साथ ही, पेंशन प्रारंभ होने की तारीख को पेंशनर के बैंक खाते में पेंशन का भुगतान ऑनलाइन कर दिया जाएगा। वित्त विभाग ने ई-पेंशन पोर्टल के जरिये ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए सभी विभागों को शासनादेश जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान ने आनलाइन सेवा पोर्टल के अनुपालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ई-पेंशन प्रबंधन के तहत पीपीओ जारी हो जाने के बाद ग्रेच्युटी, राशिकरण का भुगतान कार्मिक की सेवानिवृत्ति तारीख के बाद तीन कार्यदिवसों में हो सकेगा। तय तिथि पर पेंशनर के बैंक खाते में पेंशन का भुगतान भी आनलाइन हो जाएगा।

बुलडोजर से प्रभावित न हो गरीब : मायावती

» बसपा मुखिया ने अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। नई दिल्ली के जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को भी गहरी आपत्ति है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की मांग है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी ही नहीं, देश के किसी भी कोने में पहले अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

कहीं पर भी अतिक्रमण हटाने या फिर अवैध निर्माण तोडने में गरीब ना पिसे तो बेहतर है। बसपा मुखिया मायावती भी दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने के मामले में कूद पड़ी हैं। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण गिराने पर सुप्रीम कोर्ट की फिलहाल रोक के बाद अब मायावती ने भी बुलडोजर की आड़ में गरीबों के प्रभावित होने के मामले में हस्तक्षेप किया है। मायावती ने कहा कि जहांगीरपुरी सहित देश के अन्य राज्यों में भी अवैध निर्माण की आड़ में जो बुलडोजर चलाये जा रहे हैं,जिसमें गरीब लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकरण में सरकार को उन अधिकारियों के विरुद्ध भी सख्ती करनी चाहिये जिनके भ्रष्टाचार की वजह से ही अवैध निर्माण हो रहे हैं।

यूपी चुनाव में सीएम योगी ने खर्च किए 19.81 लाख

» चौरीचौरा से भाजपा प्रत्याशी इस मामले में सबसे आगे

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। विधानसभा चुनाव में सदर विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी प्रचार-प्रसार पर कुल 19.81 लाख रुपये ही खर्च किए। चौरीचौरा विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी सरवन निषाद चुनावी खर्च में सबसे आगे हैं। उन्होंने 32.05 लाख रुपये खर्च किए। 17 अप्रैल को चुनावी खर्च के ब्यौरे की फाइनल रिपोर्ट तैयार कर व्यय कमेटी ने निर्वाचन आयोग को भेज दिया।

रिपोर्ट तैयार कर पहले मुख्य कोषाधिकारी जनार्दन प्रसाद पांडेय ने ऑनलाइन ही व्यय प्रेक्षकों को उपलब्ध कराया था। उनकी सहमति और दस्तखत के बाद इसे निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया। चौरीचौरा विधानसभा से ही निर्दल प्रत्याशी रहे अजय कुमार सिंह ने 27.01 लाख रुपये खर्च किए हैं। वहीं सदर सीट से राइट टू रीकॉल पार्टी से प्रत्याशी राम धवन सबसे कम खर्च करने वाले प्रत्याशी हैं। रामधवन ने चुनाव प्रचार में नामांकन के समय जमा की जाने वाली जमानत राशि से भी कम महज 10 हजार रुपये खर्च किए हैं। छह विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा तो तीन में सपा प्रत्याशी खर्च में आगे हैं।

थाने में मारपीट पर एफआईआर की मांग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। जबरिया रिटायर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने 27 अगस्त 2021 को उनकी गिरफ्तारी के बाद हजरतगंज थाने में उनके साथ मारपीट तथा गाली-गलौज के संबंध में पुलिस कमिश्नर लखनऊ से एफआईआर की मांग की है। अमिताभ ने कहा है कि उन्हें 27 अगस्त को करीब 2:30 बजे घर से उठा कर करीब 3:15 बजे थाना हजरतगंज लाया गया था, जहां उनके साथ मारपीट तथा गाली-गलौज किया गया। उन्होंने कहा कि थाना हजरतगंज की जीडी संख्या 44 में साफ लिखा है कि अमिताभ को कोई जाहिर चोटें नहीं थीं। इसके विपरीत शाम 5:30 बजे सिविल अस्पताल में कराए गए मेडिकल में उनके शरीर पर 6 मल्टीपल अब्रेजन की चोटें पायी गयीं, जो अगले दिन 28अगस्त को जेल में हुए मेडिकल में भी पुष्ट हुआ। अमिताभ ने इन चोटों को थाने में हुई मारपीट का नतीजा बताते हुए तत्काल एफआईआर की मांग की है। गौरतलब है कि अमिताभ ठाकुर करीब सात महीने जेल में रहने के बाद 15 मार्च 2022 को जेल से बाहर आए हैं।

भ्रष्टाचार केस में बाराबंकी की असिस्टेंट कमिश्नर सस्पेंड

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी एक्शन में है। वाणिज्य कर सचल दल प्रभारी असिस्टेंट कमिश्नर अंजली चौरसिया को निलंबित कर दिया गया है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद यह कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। बिहार की राजधानी पटना के एक व्यापारी की शिकायत पर कमिश्नर के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच चल रही थी। सीएमओ के ट्वीटर हैंडल से भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई किए जाने संबंधी पोस्ट की गई है।

बिहार के पटना जिला में रहने वाले एक व्यापारी ने वित्त मंत्री से वाणिज्य कर अधिकारियों की व्यापारियों से मिलीभगत की शिकायत की थी। इसमें करोड़ों के घपले के गंभीर आरोप लगाए थे। व्यापारी का आरोप है कि स्क्रैप व्यापारी, प्लास्टिक दिखाकर कापर और एल्युमीनियम पर टैक्स चोरी कर रहे हैं। यही नहीं बाराबंकी में तैनात सचल दल अधिकारी अंजलि चौरसिया पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। अंजलि चौरसिया पर आरोप लगाया था कि एक हरियाणा की गाड़ी को पकड़ा था, जिसमें कापर स्क्रैप का 80 बोरियों में माल भरा था। इसमें बड़ी धनराशि का लेनदेन किया गया। बताया जाता है कि इस आरोप से संबंधित वीडियो भी विभाग को उपलब्ध कराया गया था। हालांकि उनके खिलाफ और भी कई मामलों में जांच चलने की बात कही जा रही है।

योगी सरकार बनाने जा रही अलग खेल नीति

» यूपी के हर मंडल में बनेगा स्पोर्ट्स कॉलेज या अकादमी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। केंद्र सरकार के खेलो इंडिया अभियान की तरह ही बेशक कोई अभियान शुरू न किया हो, लेकिन इस क्षेत्र में भी मैदान मारने की तैयारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय किया है कि हर मंडल में खेल महाविद्यालय (स्पोर्ट्स कालेज) या खेल अकादमी की स्थापना पीपीपी माडल पर की जाएगी। सरकार प्रदेश के लिए अलग से खेल नीति भी बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी के सामने शिक्षा क्षेत्र की जो कार्ययोजना प्रस्तुत की गई, उसमें खेल, युवा कल्याण और युवाओं के कौशल विकास का भी खाका अगले पांच वर्ष के लिए खींचा गया।

पिछले दिनों टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले देशभर के खिलाड़ियों को पुरस्कृत-सम्मानित कर चुकी योगी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देना अपनी प्राथमिकता में रखा है। इसी के मद्देनजर सीएम योगी ने मेरठ में निर्माणाधीन मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके

कुलपति खेल जगत के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ही बनाए जाने चाहिए। इस दिशा में बड़ा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के हर मंडल में खेल महाविद्यालय या खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। इसके लिए पीपीपी माडल अपनाने पर विचार किया जाएगा। यह संस्थान खेल की किसी एक-एक विधा के लिए होंगे। खेल संबंधी अवस्थापना सुविधाओं के लगातार विकास का दावा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों को और नियोजित स्वरूप देते हुए जल्द ही मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की जाए। यथाशीघ्र प्रदेश की नई खेल नीति तैयार करने का निर्देश भी दिया है, जिसमें खेल जगत के प्रोफेशनल की मदद ली जाएगी। इसी से जुड़े मंगल दलों को भी प्रोत्साहन देने की तैयारी है।

सीएम योगी ने कहा कि मंगल दल खेलकूद के साथ युवाओं को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का शानदार मंच बनकर उभरे हैं। खेल के साथ ही प्रदेश सरकार का खास जोर कौशल विकास पर है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ही इस दिशा में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार ने अगले पांच वर्षों में युवाओं के कौशल विकास के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कौशल विश्वविद्यालय (स्किल यूनिवर्सिटी) की स्थापना के लिए फिजिबिलिटी स्टडी व भूमि का चयन समय से कराया जाए। सरकार का जोर रोजगारपरक शिक्षा पर है। ऐसे में तय किया गया है कि छह माह में नई शिक्षा नीति-2020 के तहत पहले चरण में 25 हजार माध्यमिक व उच्चतर कक्षाओं के छात्रों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अब प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरस्त करने में जुटी सरकार, प्लान तैयार

» हर विधान सभा क्षेत्र में अस्पताल बनाने का लक्ष्य

» सीएम योगी ने दिए निर्देश, 14 जिलों में जल्द शुरू होगा काम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। कोरोना काल में उपजे संकट को देखते हुए योगी सरकार स्वास्थ्य महकमे को लेकर अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में सीएम योगी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरूस्त करने में जुट गए हैं। इसके लिए मंत्रियों संग प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए संकल्प लिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक सौ शैय्या अस्पताल होगा। पांच वर्षों के लिए तय चरणवार लक्ष्यों में हर जिले में निशुल्क डायलिसिस की सुविधा और प्रत्येक जिले में जिला अस्पताल के अलावा एक फर्स्ट रेफरल यूनिट की व्यवस्था भी इसमें शामिल की गई है।

योगी मंत्रिमंडल के समक्ष एनेक्सी भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेक्टर की चरणबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। बिंदुवार समीक्षा के बाद सीएम योगी ने कहा कि पिछले पांच वर्ष में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदेश में अभूतपूर्व काम हुआ है। इंसेफेलाइटिस उन्मूलन का प्रयास हो या कोविड प्रबंधन, प्रदेश को वैश्विक संस्थाओं से सराहना मिली है। एक टीम के रूप में यह प्रयास सतत जारी रखा जाए। नियोजित प्रयासों से एनएचआरएम और एनएचएम जैसी योजनाओं को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया गया है। यह शुचिता बनी रहे। भ्रष्टाचार की हर शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कठोरतम कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने अन्य लक्ष्य तय किए। उन्होंने कहा कि सभी विधान सभा क्षेत्रों में 100 शैय्या के अस्पताल की उपलब्धता कराई जाए। इसे चरणबद्ध रूप से पूरा कराएं। जिस तरह पिछले पांच वर्षों में 5000 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना की गई, उसी तरह अगले पांच वर्ष में 10,000 नए उपकेंद्र बनाने हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि हर जिले में निश्शुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि बेहतर चिकित्सा सेवाओं के लिए डाक्टरों और नर्सों की पर्याप्त तैनाती होनी चाहिए। डॉक्टर और नर्स का अनुपात एक-एक हो। आवश्यकता के अनुसार पद सृजित कर योग्य प्रोफेशनल का चयन किया जाए। पैरामेडिकल स्टाफ स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। अगले छह माह में 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करें। नियुक्ति प्रक्रिया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कराई जाएगी।

केजीएमयू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सिविल अस्पताल का विस्तार

लखनऊ स्थित केजीएमयू में क्षय रोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कराई जाएगी, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल के विस्तारीकरण की आवश्यकता बताई गई है। लखनऊ में नेशनल सेंटर फार डिजीज कंट्रोल की शाखा स्थापित करने के लिए कहा गया है। सीएम ने निर्देश दिया है कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मैटरनल एनीमिया मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना कराई जाए। यह सुनिश्चित कराएं कि सभी फर्स्ट रेफरल यूनिट में ब्लड स्टोरेज यूनिट जरूर हो।

मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में बनेंगे नर्सिंग कॉलेज

स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए तय किया है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों व जिला अस्पतालों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना कर सीटें बढ़ाई जाएंगी। संसाधन निचले स्तर तक बढ़ाने पर जोर है। हर आंगनबाड़ी केंद्र का अपना भवन होगा। इन्हें प्री-प्राइमरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। कम से कम 5000 नए आंगनबाड़ी केंद्रों बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को मिलेगा कैशलेस इलाज

योगी सरकार ने अगले सौ दिन के लक्ष्य में रखा है कि सभी राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। वहीं सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाया जाएगा। मानसिक रोगियों की सहायता के लिए निजी स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लेने का सुझाव सीएम ने दिया है। उन्होंने कहा है कि आगरा, बरेली और वाराणसी के मानसिक चिकित्सालयों में उन्मुखीकरण केंद्र खोला जाना चाहिए ताकि आमजन को मानसिक रोग के संबंध में सही-सटीक जानकारी दी जा सके।

संगठन को मजबूत करने को बसपा सुप्रीमो ने तैयार की रणनीति, कोर वोटरों पर नजर

» फिर सक्रिय की जाएगी वालंटियर फोर्स, जिलेवार एक संयोजक व दस सहसंयोजक की बनेगी टीम

» जोन स्तर पर बदली जा चुकी है जिम्मेदारी, लोक सभा चुनाव के पहले कील कांटे दुरुस्त करने की कवायद

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। यूपी विधान सभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अब बसपा प्रमुख मायावती की नजर लोक सभा चुनाव पर टिक गयी है। इसके लिए उन्होंने फिर से संगठन को मजबूत करने पर फोकस किया है। संगठन को फिर से तैयार करने के लिए बसपा वालंटियर फोर्स (बीवीएफ) पर काम करेगी। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने नए सिरे से बीवीएफ समितियों का गठन करने को कहा है। इसके तहत 28 अप्रैल तक हर जिले में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी पुरानी टीम को एक बार फिर से सक्रिय करने की योजना बनाई है। दरअसल, बसपा को सबसे बड़ी चिंता अपने कॉडर को लेकर है। विधान सभा चुनाव में बसपा का कोर वोट टूटा है। बसपा के शीर्ष नेतृत्व को चिंता है कि जो काडर वोट अभी भी पार्टी के साथ है वह विधान सभा में अपेक्षित परिणाम न आने से निराश होकर कहीं और न शिफ्ट हो जाएं। लिहाजा इसे रोकने के लिए बीवीएफ को सक्रिय किया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक जिले में बीवीएफ में एक संयोजक और 10 सहसंयोजक बनाए जाएंगे। 11 सदस्यीय इस टीम से मुख्य संगठन में जिलाध्यक्ष, विधान सभा सचिव या अन्य पदाधिकारी भी चुनने को प्राथमिकता दी जाएगी। यही समिति काडर कैपों की मॉनिटरिंग भी करेगी। बसपा ने हाल ही में जोन स्तर की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे मंडल प्रभारी नियुक्त किए हैं। बसपा थिंक टैंक का मानना है कि बड़े पदों की बजाय अब जिलों व मंडलों पर सीधे पदाधिकारियों को लोगों से कनेक्ट करने की व्यवस्था की जाए। जिससे निचले स्तर तक पार्टी का संदेश पहुंच सके।

मात्र 13 फीसदी मिला वोट

यूपी में लगभग 22 प्रतिशत दलित हैं। बसपा को इस बार तकरीबन कुल 13 प्रतिशत वोट मिले हैं। यह वोट प्रतिशत 1993 के बाद सबसे कम है। इससे साफ है कि पार्टी का अपना कोर वोटर भी पार्टी से दूर हो गया है। यह वोट बैंक भाजपा में शिफ्ट कर गया। भाजपा ने दलितों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाईं। इनका समर्थन 2014 में देखने को मिला। फिर 2017 में साथ दिया। इसके बाद 2019 में मायावती ने जब सपा के साथ गठबंधन किया तो दलित वोट उनसे छिटक गया। 2022 में दलित मायावती की बातों में नहीं आए यह वोट बैंक उनसे छिटक गया। अब 2024 की तैयारी के लिए मायावती ने नॉन दलितों को पोस्टों से हटा दिया। इसके अलावा अपने परिवार के लोगों को जिम्मेदारी दी है।

महज एक सीट मिली है बसपा को

जिस बसपा ने 2007 में उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई थी वही बसपा 10 साल में सिमटकर एक विधायक पर आ गई है। 2022 के चुनाव में सिर्फ एक विधायक (रसड़ा से उमाशंकर सिंह) ने ही जीत हासिल की है, बसपा के बाकी सभी प्रत्याशी चुनाव हार चुके हैं। गौरतलब है कि 2017 के चुनाव में बसपा के 19 विधायक थे।

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma

@Editor_Sanjay

जिद... सच की

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दरकार

सवाल यह है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता पर क्यों नहीं रखा गया? अधिकांश राज्यों में सरकारी अस्पताल बदहाल क्यों हैं? चिकित्सकों, दवाओं और जांच उपकरणों की कमी क्यों है? मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तेजी से इजाफा क्यों नहीं किया जा रहा है? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट में नाममात्र का प्रावधान क्यों है?

कोरोना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है। दूसरी लहर के दौरान हर राज्य में हाहाकार मचा रहा। ऑक्सीजन से लेकर दवाओं तक की किल्लत रही। हजारों लोगों ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। चिकित्सा सेवाओं का मजबूत आधारभूत ढांचा नहीं होने के कारण केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक बेबस दिखीं। हालांकि बाद में सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए फौरी उपाय किए और कुछ दीर्घकालीन योजनाएं भी बनायी हैं। बावजूद इसके राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की जरूरत है। सवाल यह है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता पर क्यों नहीं रखा गया? अधिकांश राज्यों में सरकारी अस्पताल बदहाल क्यों हैं? चिकित्सकों, दवाओं और जांच उपकरणों की कमी क्यों है? मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तेजी से इजाफा क्यों नहीं किया जा रहा है? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट में नाममात्र का प्रावधान क्यों है? सियासी दलों के एजेंडे में स्वास्थ्य को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती है? गरीबों को आयुष्मान और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पाता है? क्या लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है?

जनसंख्या के लिहाज से दुनिया के दूसरा बड़े देश भारत में चिकित्सा सेवाओं की हालत बेहद चिंताजनक है। हालांकि महामारी के बाद चिकित्सा क्षेत्र में कुछ सुधार किए गए हैं लेकिन अभी भी ये पर्याप्त नहीं है। मसलन, यूपी में अस्पतालों की हालत खराब है। यहां चिकित्सकों की कमी है। अस्पतालों में दवाओं और जांच उपकरणों की किल्लत है। लिहाजा लोगों को जांच के लिए पंद्रह-पंद्रह दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक नदारद रहते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टीकाकरण केंद्र बनकर रह गए हैं। चिकित्सकों के हजारों पद खाली पड़े हैं। अधिकांश गरीबों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सरकार ने कुछ नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। दरअसल, भारत अभी भी उन देशों की श्रेणी में हैं, जहां स्वास्थ्य सेवा में सार्वजनिक खर्च का अनुपात बहुत ही मामूली है। हमारे देश में यह सकल घरेलू उत्पादन का लगभग डेढ़ प्रतिशत है, वहीं प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के कारण हर साल लाखों लोग गरीबी की चपेट में आ रहे हैं। इस स्थिति में आयुष्मान भारत योजना तथा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से लोगों को राहत मिल सकती है। जाहिर है राज्य सरकारों को चाहिए कि वह इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन मुहैया कराए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही लोगों को सस्ता और बेहतर इलाज मिल सके।

संजय

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

सुधारों से खुलेगी शीघ्र न्याय की राह

अनूप भटनागर

केंद्र सरकार भले ही बार-बार दावा करे कि न्यायपालिका की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि जनता को शीघ्र न्याय मिल सके लेकिन हकीकत यह है कि उसकी प्राथमिकता-सूची में न्यायपालिका व न्यायिक सुधार शामिल नहीं हैं। विधि आयोग के गठन के बावजूद इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति में करीब दो साल विलंब और मुख्यमंत्रियों तथा मुख्य न्यायाधीशों के द्विवार्षिक सम्मेलन का समय पर न हो पाना इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। न्यायपालिका से जुड़े विषयों के प्रति सरकार की गंभीरता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 24 फरवरी, 2020 को 22वें विधि आयोग के गठन के बावजूद इसके अध्यक्ष व सदस्यों की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका तक दायर की थी जो अभी लंबित है लेकिन विधि आयोग अभी भी अध्यक्ष विहीन है।

विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने बीती फरवरी में संसद को सूचित किया था कि नए विधि आयोग को समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर काम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल सकेगा क्योंकि इसके अध्यक्ष व सदस्यों की अभी नियुक्ति होनी है। इसी तरह, देश में हर दो साल के अंतराल पर न्यायिक सुधारों पर विचार के लिए मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन होता है लेकिन इस बार छह साल बाद 30 अप्रैल को इसका आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ ही प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण और अन्य न्यायाधीश भी संबोधित करेंगे। यही नहीं, सरकार के दावों के बावजूद आज भी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 387 पद रिक्त हैं जबकि इनमें लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समय देश के उच्च न्यायालयों में 58,88,940 मुकदमें लंबित हैं जिनमें दीवानी मामलों की संख्या ही 42,52,232 है। यही स्थिति निचली अदालतों की है जिनमें करीब चार करोड़ 12 लाख मुकदमे लंबित हैं। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण बार-बार इस तथ्य को दोहरा रहे हैं कि लंबित मुकदमों की भारी-भरकम संख्या और न्यायाधीशों की कमी से वादकारियों में यह धारणा बनती जा रही है कि अदालत में तो उन्हें सालों बाद न्याय मिलेगा। न्यायमूर्ति रमण का मत है कि न्याय तक सुगमता से पहुंच तभी संभव होगी जब हम पर्याप्त संख्या में अदालतें स्थापित कर उनमें बुनियादी सुविधाएं दें ताकि

वादकारी तेजी से न्याय मिलने के यकीन के साथ अदालत आ सकें। अधीनस्थ न्यायपालिका की स्थिति यह है कि देश के 651 जिलों में 3,377 अदालत परिसर हैं, जिनमें कुल 21,035 अदालतें और 17,812 पदासीन न्यायाधीश तथा न्यायिक अधिकारी हैं। जिलों में कम से कम 618 अदालतें खाली हैं। इसकी वजह न्यायाधीशों के पद रिक्त होना है। प्रधान न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायपालिका के कामकाज में सुधार तथा न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम जब रिक्त स्थानों पर नियुक्ति या फिर अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीशों को पदोन्नति देकर उच्च न्यायालय में नियुक्त करने की सिफारिश करता है तो केन्द्र सरकार कई-कई महीने उस पर आगे कार्यवाही नहीं करती है। इस रवैये पर शीर्ष अदालत ने कई बार अपनी नाराजगी व्यक्त की लेकिन स्थिति में बहुत अधिक सुधार होता नजर ही नहीं आता है। न्यायमूर्ति रमण, जो इस साल 26 अगस्त को 65 साल की आयु में देश के प्रधान न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, का मानना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है और इस आयु सीमा को बढ़ाने के सवाल पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा बढ़ाने का मसला लंबे समय से चर्चा में है। पहले भी कई पूर्व प्रधान न्यायाधीश और यहां तक कि अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल भी यह आयु सीमा बढ़ाने के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं। पूर्व न्यायाधीशों का मत रहा है कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित मुकदमों का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के द्विवार्षिक सम्मेलन में न्यायिक सुधारों, न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर त्वरित नियुक्तियां तथा मुकदमों की लंबित संख्या कम करने के बारे में दिये जाने वाले सुझावों को प्राथमिकता देगी।

महंगाई पर नियंत्रण लगाए सरकार तभी मिलेगी राहत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। महंगाई आसमान छू रही है। सब्जी, तेल व अनाज के दामों में आग लगी है मगर सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। आम जनता चाह रही है कि सरकार महंगाई रोके तो ही घर का खर्च चलेगा। 4पीएम के संवाददाता क्षितिज कान्त ने महंगाई के मुद्दे पर जानी लोगों की राय।

महेश मौर्य का कहना है सब्जियों में रेट थोड़ा कम जरूर हुए हैं लेकिन नींबू अभी भी 200 से 240 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। इसके कारण मंडी में सन्नाटा रहता है। बिक्री न होने के कारण हजार-पांच सौ का रोजाना नुकसान हो रहा है। महंगाई के कारण 60 फीसदी व्यापार ठप पड़ा है। इससे काफी घाटा हो रहा है। संदीप कहते हैं कि लगभग 70 प्रतिशत सब्जी बिक पाती है। हर दिन 25-30 फीसदी का नुकसान हो रहा है। नींबू की मांग ज्यादा है और उत्पादन कम हो रहा है इसलिए नींबू बहुत महंगा है। लगभग 60 रुपए प्रति पाव बिक रहा है। कारोबार मंदा होने के कारण घर जैसे तैसे चला रहे हैं। अक्सर ग्राहकों से भी बहस हो जाती है।

अभिषेक यादव ने कहा कि मंडी में सन्नाटा है। ग्राहक काफी कम हो गए हैं। लिहाजा लागत भी नहीं निकल रही है। ऐसे हालात रहे तो दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। सुबह से दोपहर तक केवल 4 से 5 ग्राहक ही आये है। सबसे सस्ता आलू बिक रहा है 15 रुपया, जिसे आजकल लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। फूलचंद कहते हैं कि महंगाई ने हालत खराब कर दी है। पेट्रोल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। इसके कारण आम आदमी परेशान हो गया है। सरकार को चाहिए कि वह महंगाई कम करें। शुभम सिंह कहते हैं कि महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है। सरकार महंगाई पर नियंत्रण करे तभी कुछ राहत मिलेगी। दिव्यांशु तिवारी कहते हैं कि महंगाई के कारण गाड़ी का उपयोग कम कर दिया है। पहले सौ से डेढ़ सौ का पेट्रोल गाड़ी में डलवाता था अब 60 रूपये का पेट्रोल भरवा रहा हूं। महंगाई ने पूरा बजट बिगाड़ दिया है। डीजल के दाम बढ़ने से अन्य वस्तुएं भी महंगी हो गयी है। आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुरगेशन का कहना है कि मैं दक्षिण भारतीय हूं। कोरोना के कारण पूरा धंधा चौपट हो गया। महंगाई के चलते दुकान का खर्च छोड़िए अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं निकल पा रहा है। रेट बढ़ाने पर ग्राहक नाराज हो जाते हैं। सरबजीत यादव कहते हैं कि मैं पहले 30 सिलेंडर की सप्लाई करता था वहीं अब दस कर रहा हूं। महंगाई के बावजूद पगार नहीं बढ़ी है। पहले कुछ बचत हो भी जाती थी अब तो कमाई अठन्नी है और खर्चा रुपैया हो गया है। आम आदमी अपना जीवन कैसे चलाए।

गर्मियों में जरूर खाएं तोरई मिलेंगे कई फायदे

गर्मियों के मौसम में तोरई का सेवन सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। तोरई भारत की उन डिशेज में से एक है, जिसे लगभग हर घर में बनाया जाता है। यह अलग बात है कि यह आमतौर पर लोगों की पहली पसंद नहीं होती। तोरई दो प्रकार की होती हैं - एक चिकनी सतह के साथ और दूसरी उभरी सतह के साथ। लोग इसे कई नामों से पुकारते हैं, हिंदी में तुरई, बंगाली में झिंगे, तेलुगु में बीरकाया और तमिल में पीरकंगई के नाम से इसे जाना जाता है। यह एक हरे रंग की सब्जी है, जिसका स्वाद हल्का होता है। कई लोगों को तोरई की सब्जी का स्वाद पसंद नहीं आता लेकिन यह हमारे सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। तोरई में फाइबर, पानी, विटामिन 2, विटामिन-12, आयरन, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई गुण पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं तोरई के फायदों के बारे में।

एनीमिया

तोरई के सेवन से आयरन की कमी के कारण होने वाले एनीमिया को ठीक करने में मदद मिलती है। इसके अलावा, तोरई में विटामिन-बी6 भरपूर मात्रा में होता है, जो आयरन के साथ-साथ शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

त्वचा के लिए फायदेमंद

त्वचा की सुंदरता का राज पेट से हो कर जाता है। पेट में जरा सी गड़बड़ी आपके चेहरे पर दाने, मुंहासे, बेजान त्वचा जैसी कई समस्याएं पैदा कर सकती हैं। पेट के लिए तोरी बहुत फायदेमंद होती है। हफ्ते में दो से तीन बार तोरई खाने से पेट साफ रहता है।

इम्युनिटी बढ़ाती है

तोरई में विटामिन-सी, आयरन, मैग्नीशियम, थियामिन, रिबोफ्लेविन और जिंक होता है, जो आपकी इम्युनिटी बढ़ाता है।

वजन घटाने में कारगर

वजन घटाने के लिए तोरई काफी फायदेमंद है। तोरई में कैलोरी काफी कम होती है और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। इसके सेवन से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है और आपको भूख कम लगती है।

ब्लड शुगर

तोरई के सेवन से शरीर के इंसुलिन को नियंत्रित किया जा सकता है। यह आपके शरीर में ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करती है।

बॉडी को हाइड्रेट

तोरई का सेवन करने से आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है।

हंसना मना है

एक शराबी सड़क पर जा रहा था अचानक फिसलकर वह कीचड़ में गिर गया उसी वक्त बिजली चमकी तो... शराबी बोला-हे भगवान एक तो पहले कीचड़ में गिरा दिया और अब फोटो भी खींच रहे हो।

टीटू- हमारे पड़ोसी बड़े खराब हैं. शीटू- क्यों...क्या हुआ? टीटू- कल रात 3:00 बजे वह हमारे घर का दरवाजा पीटने लगे... शीटू- रात 3:00 बजे... यह भी कोई बात हुई? टीटू- वही तो शुक्र है कि मैं जगा हुआ था और ढोलक बजाना सीख रहा था...

अध्यापक- बताओ बच्चों...दिन में तारे किस समय दिखाई देते हैं ? एक छात्र ने उत्तर दिया- जब तमाचे पड़ते हैं...

गोलू- घोड़ी पर दूल्हा ही क्यों बैठता है दुल्हन क्यों नहीं? टोलू- घोड़ी पर बैठाकर दूल्हे को भागने का आखिरी मौका दिया जाता है।

डॉक्टर- आपका लड़का रामू पागल कैसे हो गया? पिता- वो पहले जनरल बोगी में सफर करता था। डॉक्टर- तो? पिता- लोग बोलते थे थोड़ा खिसको- थोड़ा खिसको, तभी से ये पूरा खिसक गया।

पापा - बेटा, अमेरिका में 15 साल के बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। चिंटू - लेकिन पापा, भारत में तो एक साल का बच्चा भागने भी लगता है।

कहानी — जीत किसकी

बारशाह अकबर जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। फौज पूरी तरह तैयार थी। बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ गए। साथ में बीरबल भी थे। बादशाह ने फौज को जंग के मैदान में कूच करने का निर्देश दिया। बादशाह आगे-आगे थे, पीछे-पीछे उनकी विशाल फौज चली आ रही थी। चारों ओर गंभीरता थी। रास्ते में बादशाह की जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि जंग में जीत किसकी होगी, बीरबल। बीरबल ने कहा- हुजूर, इस सवाल का जवाब तो मैं जंग के मैदान में पहुंचकर ही दूंगा। कुछ देर बाद फौज जंग के मैदान में पहुंच गई। बीरबल ने चारों ओर देखा फिर कहा हुजूर, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं और जवाब यह है कि जीत आपकी ही होगी। यह तुम अभी कैसे कह सकते हो, जबकि दुश्मन की फौज भी बहुत विशाल है। उसके पास भी अच्छे योद्धा हैं। कई फौजों को इस फौज ने पराजित किया है। उसके सेनापति का बड़ा नाम है। बादशाह ने शंका जाहिर की। बीरबल ने कहा- हुजूर! दुश्मन हाथी पर सवार है और हाथी तो सूंड से मिट्टी अपने ऊपर ही फेंकता है तथा अपनी ही मस्ती में रहता है, जबकि आप घोड़े पर सवार हैं और घोड़ों को तो गाजी मर्द कहा जाता है। घोड़ा आपको कभी धोखा नहीं देगा। उस जंग में जीत बादशाह अकबर की ही हुई। जीत के बाद बादशाह ने बीरबल के अनुमान की सराहना की।

इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा : अधिकांश युद्ध बुद्धि-कौशल, फौज की मारक क्षमता और सेनापतियों की सूझबूझ से ही जीते गए हैं। बीरबल जो स्वयं भी एक अच्छे सेनापति थे, वे इस बात को जान गए थे कि यह युद्ध हाथियों के दम पर नहीं, घोड़ों की चपलता से ही जीता जा सकता है। इसलिए उन्होंने बादशाह अकबर द्वारा वह युद्ध जीतने की भविष्यवाणी कर दी थी, जो बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई।

7 अंतर खोजें

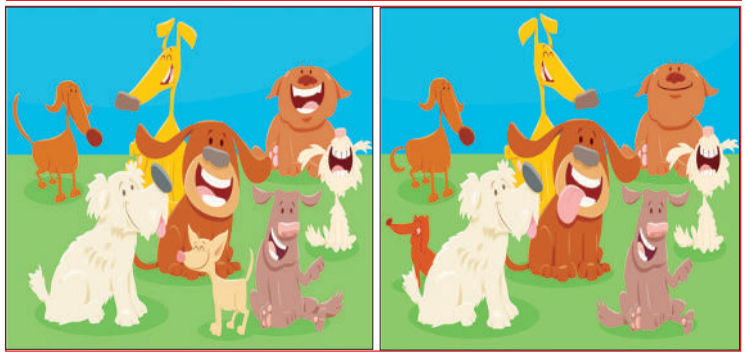

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

आज के दिन आप अपने पार्टनर से अपने दिल की बात साझा कर सकते हैं। इससे आप दोनों के रिश्ते में गहराई आएगी। इसके अलावा आज आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं।

वृषभ

इस दिन आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताना चाहेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको अपने काम की वजह से समय ही ना मिले। इस पर आपको काफी गुस्सा भी आएगा।

मिथुन

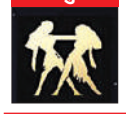

आज इस राशि के जातकों को अपने पार्टनर से बातें करने का अवसर बन रहा है। इससे आपके रिश्ते में गहराई आएगी और आप उसके प्यार की महत्ता को समझ पाएंगे।

कर्क

इस राशि के लोगों का पिछले दिनों कई लोगों ने दिल तोड़ा है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद के लिए समय निकालें। आप इस बात पर विचार करें कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए।

सिंह

इस राशि के जातकों का हाल ही में नए पार्टनर से मुलाकात हुई है। आज के दिन आप उसके साथ काफी समय बिताएंगे और बातें करेंगे। इससे आपको अपने साथी को समझने में मदद मिलेगी।

कन्या

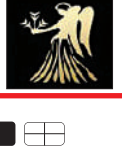

इस राशि का लोगों का अपने पार्टनर से किसी बात पर विवाद हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप सामने वाले व्यक्ति पर क्रोधित ना हों और ध्यान से उसकी बातें सुनें।

तुला

आपकी यह मुलाकात काफी समय के बाद हो रही है जिससे आपको काफी खुशी मिलेगी। साथ ही आप दोनों एक-दूसरे के साथ काफी समय बिताएंगे और प्यार साझा करेंगे।

वृश्चिक

आज के दिन आपके मन में प्यार को लेकर ढेर सारे सवाल खड़े होंगे। लेकिन आपको धैर्य रखने की जरूरत होगी और आने वाले दिनों में आपको इन सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे।

धनु

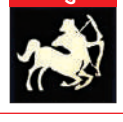

धनु राशि के जातक इस दिन खुद को थोड़ा अकेला महसूस कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि खुद को शांत रखें और दोस्तों या परिवार वालों के साथ समय बिताएं।

मकर

आज आप अपने प्यार का इजहार करेंगे और इसमें आपको काफी सफलता भी मिलेगी। इसके अलावा आपको अपने परिवार वालों का साथ भी मिलेगा और उनसे अपनी बातें आसानी से कह पाएंगे।

कुम्भ

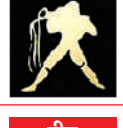

आप अपने साथी की काफी मदद करेंगे। इससे आप दोनों को ही काफी खुशी का अहसास होगा। इसके अलावा आपको अपने पार्टनर का भरपूर प्यार आपको मिलेगा।

मीन

आज थोड़ा सकारात्मक रहने की जरूरत हैं। क्योंकि, आज का दिन प्रपोज करने के लिए काफी बेहतर है। ऐसे में जरूरत है कि आप आगे बढ़ें और पूरी ईमानदारी के साथ अपने दिल की बातें साझा करें।

बॉलीवुड | मन की बात

जयेशभाई जोरदार मेरे दिल के सबसे करीब : रणवीर

रणवीर सिंह का कहना है कि उनकी आने वाली फिल्म जयेशभाई जोरदार उनके दिल के सबसे करीब है, जिसमें उन्होंने देश के सबसे बड़े निर्देशकों के साथ काम किया है। रणवीर कहते हैं कि मैं धन्य और भाग्यशाली हूं कि मुझे यह स्क्रिप्ट मिली जो लोगों को प्रभावित करेगी। मैं आभारी हूं। जिन भूमिकाओं को मैंने पर्दे पर जीवंत किया है, मुझे उन पर भी गर्व है।

मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर मुझे देश का सबसे अच्छा अभिनेता-मनोरंजक बनना है, तो मुझे ऐसे काम करने होंगे जो कोई न करता हो। उन्होंने आगे कहा, जयेशभाई जोरदार एक ऐसी फिल्म है जिसका हिस्सा बनकर मुझे बहुत मजा आया क्योंकि इसने मुझे फिर से एक ऐसा चरित्र निभाने के लिए प्रेरित किया, जिसका हिंदी सिनेमा में कोई संदर्भ बिंदु नहीं था। रणवीर ने जोर देकर कहा कि जयेशभाई जैसा किरदार पहले नहीं देखा गया है। रणवीर आगे कहते हैं कि उम्मीद है कि जयेशभाई पर्दे पर वीरता की परिभाषा बदल देगा और उम्मीद है कि सबसे मनोरंजक और प्रफुल्लित करने वाले अंदाज में लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ेगा। जयेशभाई के चरित्र और फिल्म से उनकी अपेक्षाओं के बारे में उन्हें क्या पसंद है, इस बारे में रणवीर कहते हैं कि वह तेज दिमाग वाला है और उसका दिल साफ है। स्क्रिप्ट सिर्फ उल्लेखनीय है। आपको ऐसी फिल्में हर दिन नहीं मिलती है। जयेशभाई एक दुर्लभ प्रोजेक्ट है। मुझे आशा है कि हम इस फिल्म के साथ सभी का मनोरंजन करने का प्रबंधन करेंगे क्योंकि यह वास्तव में सभी को आनंद देगी।

अमेजन पर इंडियन पुलिस फोर्स लेकर आए रोहित शेट्टी

खाकी में दिखा सिद्धार्थ मल्होत्रा का कॉप अंदाज, लोग कर रहे तारीफें

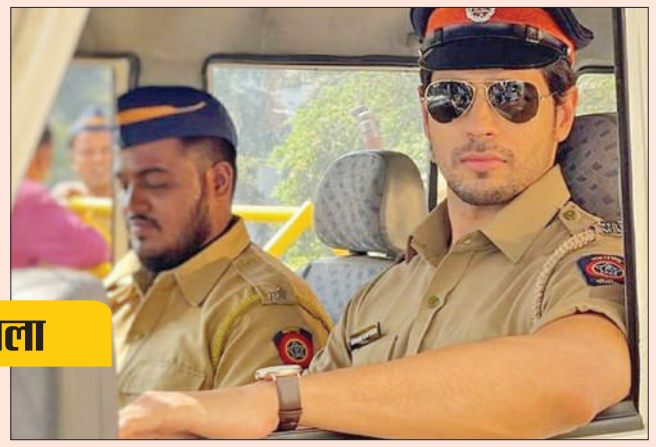

बॉलीवुड | मसाला

रोहित शेट्टी अपने फैंस के लिए नई कॉप सीरीज लेकर आए हैं। उनकी वेब सीरीज का नाम इंडियन पुलिस फोर्स है। इस सीरीज से रोहित शेट्टी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपना डेब्यू कर रहे हैं। रोहित शेट्टी कॉप ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। वह सिंघम, सिंबा और सूर्यवंशी जैसी सफल कॉप ड्रामा फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। अब उन्होंने कॉप वेब सीरीज बनाने का फैसला किया है। रोहित शेट्टी की वेब सीरीज में नए पुलिस ऑफिस सिद्धार्थ मल्होत्रा होंगे। निर्देशक यह सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के लिए बना रहे हैं। बुधवार को अमेजन प्राइम वीडियो ने एक खास वीडियो शेयर कर इंडियन पुलिस फोर्स के घोषणा की है। इस वीडियो में रोहित शेट्टी के अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा कॉप लुक में नजर आए हैं। वीडियो के अनुसार इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग शुरू कर दी गई है। यह वेब सीरीज आठ एपिसोड की होगी, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक्शन, सस्पेंस और देशभक्ति अंदाज देखने को मिलेगी। अपनी इस वेब सीरीज की घोषणा करते हुए रोहित शेट्टी ने कहा, इंडियन पुलिस फोर्स मेरे लिए बहुत खास है और मैं सालों से इस पर काम कर रहा हूं। मुझे इस कहानी में जान फूंकने के लिए अमेजन प्राइम वीडियो के साथ सहयोग करने की खुशी है, जो भौगोलिक और भाषाई बाधाओं को पार कर जाएगी, जिससे मुझे दुनिया भर के दर्शकों को इसे दिखाने का अवसर मिलेगा।

रोहित शेट्टी ने आगे कहा, मैं इस वेब सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। मैंने हमेशा एक्शन एंटरटेनमेंट के दायरे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और इस सीरीज के साथ मुझे विश्वास है कि हम एक नया बेंचमार्क बनाएंगे। आपको बता दें कि रोहित के अपनी कॉप यूनिवर्स की शुरुआत अभिनेता अजय देवगन की फिल्म सिंघम के साथ की थी।

काजल अग्रवाल के घर गूंजी किलकारी

काजल अग्रवाल ने शादी के 2 साल बाद एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। 'सिंघम' फिल्म से लोगों के दिलों में खास पहचान बना चुकीं एक्ट्रेस के घर एक नन्हें से बच्चे की किलकारी गूंज उठी है। काजल के मां बनने की जानकारी मिलते ही बधाइंयों का तांता लग गया है। काजल और उनके हस्बैंड गौतम किचलू के लिए आज का दिन खुशियों से भरा हुआ है, क्योंकि उनके घर एक नन्हा मेहमान आया है। एंटरटेनमेंट जगत में इन दिनों खुशियां ही खुशियां छाई हुई है। अभी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी की बधाई मिल ही रही है कि इसी बीच काजल ने भी गुडन्यूज देकर फैंस को खुश कर दिया। हाल ही में मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह भी मां बनी हैं। भारती और उनके हस्बैंड हर्ष लिंबाचियां के घर की खुशियों के बाद अब काजल ने भी खुशखबरी दे दी है। काजल अग्रवाल ने अपनी प्रेग्नेंसी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस को जानकारी दी थी। काजल ने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान अपना ख्याल रखा और साथ-साथ में एंडोर्समेंट भी करती रहीं। काजल अग्रवाल के मम्मी बनने की खबर सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने भी कंफर्म की है। काजल और गौतम किचलू की तस्वीर शेयर कर लिखा 'बेबी बॉय'। काजल के मां बनने की खबर मिलते ही फैंस मां और बच्चे की कुशल-मंगल की कामना के साथ बधाई दे रहे हैं। फरवरी में काजल अग्रवाल के गोद भराई की रस्म धूमधाम से हुई थी। इसकी तस्वीरें काजल ने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। बनारसी साड़ी में मां बनने की खुशी उनकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी।

अजब-गजब | महिला ने जाहिर की अनोखी अंतिम इच्छा, बोली-

मेरी मौत पर थोड़ी सी पीकर आएं और सिर्फ 20 मिनट रोएं

हर इंसान की मौत से पहले एक अंतिम इच्छा होती है और वह चाहता है कि मरने के बाद उसके शव के साथ वैसा ही किया जाए जैसा वह चाहता है। लेकिन लंदन की एक महिला ने अपनी अंतिम इच्छा में कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस महिला ने सोशल मीडिया में एक वीडियो साझा किया है। इसमें उसने कहा है कि उसकी मौत पर कोई भी 20 मिनट से ज्यादा न रोए। यही नहीं इस महिला ने ये भी कहा है कि उसकी मौत पर थोड़ी सी पीकर ही आएं। इसके अलावा महिला ने अपनी मौत पर ताबूत में मेकअप का सामान रखने की इच्छा भी जताई है।

इस महिला की अंतिम इच्छा महाकवि हरिवंश राय बच्चन की कृति मधुशाला में प्रकट की गई अंतिम इच्छा से कुछ मिलती जुलती है। महिला की अंतिम इच्छा कितनी पूरी होगी, इसके बारे में तो कहना मुश्किल है लेकिन लोग महिला की इस अंतिम इच्छा का वीडियो देखकर हैरान जरूर हैं, क्योंकि उस पर अमल कराने की कोई

कानूनी या सामाजिक बाध्यता नहीं होती। हालांकि, अंतिम इच्छा प्रकट करने वाले शख्स के परिजन उसकी पूर्ति करते हैं या नहीं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। हालांकि इसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

महिला ने जाहिर की ये अंतिम इच्छा

दरअसल, लंदन की रहने वाली इस महिला ने अपनी अंतिम इच्छा में कहा है कि मेरी अंत्येष्टि में शामिल होने वाले अपनी पहचान के लिए नया या पुराना फोटो आईडी लेकर जरूर आएं। इसके अलावा वो ताबूत में मेकअप का सामान यानी फाउंडेशन, लिपिस्टिक, सुरमा आदि भी रखें। इस महिला ने ये भी कहा है कि अंतिम संस्कार में आने वाले सभी लोग च्यूइंगम खाकर आएं, हालांकि मैं उस वक्त सूंघ नहीं सकूंगी, लेकिन मेरी इच्छा का सम्मान करें।

यही नहीं महिला ने अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के बारे में कहा है कि वो सभी रंगीन कपड़े पहनकर आएं। अंतिम खाना हाथों से बना हो, इसमें चिकन मैक्रोनी आदि न हो। इसके अलावा अंतिम यात्रा में शामिल होने वालों को शराब के दो पैग लगाकर आने को भी कहा गया है। इसके अलावा महिला ने कहा है कि कम पीने वाले अपने घर लौट जाएं। इसके अलावा महिना ने कहा कि उसकी मौत पर किसी को भी 20 मिनट से ज्यादा विलाप करने की इजाजत नहीं होगी।

दुनिया की सबसे पतली इमारत, तेज हवा से डोलने लगती है 84 फ्लोर की बिल्डिंग!

दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के बारे में आपने सुना होगा और इससे जुड़ी समस्याओं को भी आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप उस इमारत के बारे में जानते हैं, जो दुनिया में सबसे पतली है? वो इमारत, जो हवा के तेज झोंकों से भी डोलने लग सकती है। ऐसी इमारत अमेरिका के मनहट्टन में मौजूद है, लेकिन क्या कोई यहां रहने की भी जुर्रत करता है? 84 फ्लोर वाली इस बिल्डिंग का रेशियो 24:1 है और ये दुनिया की सबसे पतली इमारत बताई जा रही है। Steinway Tower नाम की ये बिल्डिंग इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। अमेरिका में वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सेंट्रल पार्क टॉवर के बाद ये तीसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है और दुनिया की इतनी ऊंची इमारतों में से सबसे पतली भी। 1428 फीट ऊंची इस बिल्डिंग की चौड़ाई महज 60 फीट है, जो अपने आपमें अजूबा है। Steinway Tower आर्किटेक्चर के मामले में हैरान कर देने वाली बिल्डिंग (WorldÓs Thinnest Skyscraper) है। द गार्जियन न्यूजपेपर ने इसकी तुलना कॉफी स्टरर से की है। इस बिल्डिंग को दुनिया की सबसे मजबूत कंक्रीट से बनाया गया है। साल 2015 को न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए इसके इंजीनियर रॉवन विलियम्स (Rowan Williams Davis) ने कहा था कि 1000 फीट ऊंचा टॉवर 100 मील/घंटा की रफ्तार से चल रही हवा में लहरा सकता है, हालांकि इसके अंदर रहने वाले लोग इसे महसूस नहीं कर पाएंगे। पतली और ऊंची बिल्डिंगों का चलन हॉन्ग कॉन्ग में 1970 के दौर में शुरू हुआ था लेकिन अब ये अमेरिका में भी बनाई जा रही हैं। हालांकि इन बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों को पूरे शहर का एक बेहतरीन व्यू मिलता है, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकती हैं। इससे पहले पतली बिल्डिंग्स में कई दिक्कतें आ चुकी है। इस बिल्डिंग में एक स्टूडियो अपार्टमेंट की भी कीमत 7.75 मिलियन है, जबकि पेंटहाउस की कीमत 66 मिलियन यानि अरबों में है। यानि यहां रहने वाले लोगों के लिए अमीर होना जरूरी है।

योगी सरकार का बड़ा फैसला

यूपी बोर्ड: अब नए पैटर्न से होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं

» कक्षा 9 और 11 में लागू होगा इंटर्नशिप प्रोग्राम

» विद्यालयों के मूल्यांकन पर भी दिया गया जोर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा-2023 नए पैटर्न से होगी। परीक्षा में एक प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय दिया जाएगा, जिसका उत्तर ओएमआर शीट पर देना होगा। 2025 से इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में भी यह पैटर्न लागू किया जाएगा। वहीं विद्यार्थियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में इंटर्नशिप कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के बाद माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन होने जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा का नया पैटर्न 2023 का नया सत्र शुरू होने के पहले लागू करें। 12वीं में बोर्ड परीक्षा का नया पैटर्न 2025 तक लागू करने की जरूरत है ताकि संरचनात्मक शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार का कार्य पूरा हो सके। मंत्रिपरिषद के समक्ष शिक्षा विभाग की कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण पर सीएम ने निर्देश दिया कि पांच वर्षों के भीतर सभी असेवित क्षेत्रों में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना के लिए अभी से रणनीति बनाकर कार्यवाही शुरू करें। सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम, रियल टाइम मानीटरिंग, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम और एकीकृत डाटा प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। साथ ही कक्षा नौ व 11 में इंटर्नशिप प्रोग्राम, रोजगारन्मुख कौशल शिक्षा व सर्टिफिकेशन, राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना की दिशा में कार्यवाही शुरू कराएं। पांच वर्ष पर विद्यालयों का मूल्यांकन और सर्टिफिकेशन भी करें।

रोजगारपरक शिक्षा की कार्ययोजना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाए। सौ दिनों में 120 राजकीय महाविद्यालयों में ई-लर्निंग पार्क की नियमावली बनाकर पोर्टल का शुभारंभ करें। साथ ही निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल, पांच राजकीय महाविद्यालयों और तीन राज्य विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेटर्स का शुभारंभ करें।

संस्कृत शिक्षा निदेशालय का होगा गठन

दो वर्षों के भीतर संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन किया जाएगा। एकीकृत डाटा प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी। संस्कृत को तकनीकी के माध्यम से रोजगार से जोड़ने के लिए 180 घंटे का सर्टिफिकेट और 360 घंटे का डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की ओर से ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। संस्कृत की पारंपरिक विद्या, कर्मकांड, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अर्चक और पुरोहित तैयार करने की दिशा में कार्यवाही तेज की जाएगी।

रिश्वत लेते जिला अभिहित अधिकारी गिरफ्तार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

रामपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कार्यालय के अभिहित अधिकारी कुलदीप सिंह को बरेली से आई विजिलेंस टीम ने बुधवार को 30 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया।

विजिलेंस टीम ने यह कार्रवाई अजीमनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बढ़पुरा शुमाली निवासी भगवत पुत्र सोमपाल सिंह की शिकायत पर की है। वह मीट व्यापारी हैं। उनका मीट ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस था, जो निलंबित कर दिया गया था। लाइसेंस बहाली के लिए उन्होंने कलक्ट्रेट स्थित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में आवेदन किया। आरोप है कि अभिहित अधिकारी द्वारा लाइसेंस बहाली के नाम पर उनसे 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई। मीट व्यापारी ने इसकी शिकायत एसपी विजिलेंस बरेली से कर दी। एसपी विजिलेंस के आदेश पर एक टीम बुधवार को रामपुर पहुंच गई। टीम ने शिकायतकर्ता को रुपये दिए और अधिकारी को कलक्ट्रेट के बाहर आवास विकास गंगापुर में सेठी वकील के आवास के पास बुला लिया। वहां शिकायत कर्ता से रुपये लेते हुए अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लिया।

गाजियाबाद में डबल मर्डर से सनसनी

» वेव सिटी के पास दो युवकों को गोलियों से भूना

» घटना के कारणों का नहीं चला पता, पुलिस कर रही मामले की जांच

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

गाजियाबाद। बदमाशों ने वेव सिटी सेक्टर-4 के गेट के पास दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके से पुलिस को आठ कारतूस और खोखे बरामद हुए हैं। दोनों मृतकों की पहचान जितेंद्र और हरेंद्र चंदेला उर्फ चेतन थाना बादलपुर (ग्रेटर नोएडा) के रूप में हुई है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं डबल मर्डर की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गयी है।

एसएसपी मुनिराज ने बताया कि बुधवार की देर रात वेवसिटी सेक्टर-4 के गार्ड ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी कि क्षेत्र के एक खाली प्लाट के पास दो शव पड़े हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके

पर पहुंची तो दो युवकों को गोली लगी थी। दोनों मृत थे। तलाशी लेने पर मिले मोबाइल से उनकी पहचान हुई। एसएसपी मुनीराज ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोनों व्यक्ति यहां कैसे आए और कौन-कौन मौजूद था, किसने और क्यों हत्या की है। इन सब बिंदुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है। उन्होंने बताया कि वारदात के खुलासे के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है। दोनों के परिजनों को सूचित किया गया है। मृतकों की पहचान जितेंद्र पुत्र मदन निवासी मच्छा डेरी व हरेंद्र चंदेला उर्फ चेतन पुत्र बिसंबर निवाली गिरधपुर के रूप में हुई है। दोनों की उम्र 30 से 35 साल के बीत बताई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोली मारने के बाद बदमाश फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है।

वाराणसी: महिला ने दूसरी महिला को फावड़े से काटा

वाराणसी। कपसेठी थाना क्षेत्र के तक्खू बावली में एक महिला ने दूसरी महिला को आज सुबह फावड़े से काट कर मार डाला। राखी (30) ने 45 वर्षीय महिला को और सुबह घर में बुलाकर गर्दन पर वार कर फावड़े से काटकर मार डाला। महिला पंचायत चुनाव में प्रधान पद की प्रत्याशी भी रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार मृत महिला के दो बच्चे हैं। हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतका ब्यूटी पार्लर चलाने का काम करती थी। संभवतः इसी वजह से घर पर बुलाने पर चली गई होगी। इस दौरान विवाद होने की वजह से मारपीट और फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला वहीं मौजूद रही। आरोपी महिला के मौजूद रहने की वजह से मौके पर पहुंची पुलिस प्रारंभिक पूछताछ के बाद आरोपी महिला को लेकर थाने चली गई।

मुख्तार पर ईडी का शिकंजा, एलडीए से मांगा संपत्तियों का ब्योरा

» जेल में बंद पूर्व विधायक के संपत्तियों की तलाश में जुटी जांच एजेंसी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़ी लखनऊ की संपत्तियों की तलाश तेज हो गई है। ईडी ने मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के नाम से दर्ज लखनऊ की संपत्तियों का ब्योरा मांगा है। ईडी का पत्र मिलते प्राधिकरण में हड़कंप मच गया। मानचित्र और रजिस्ट्री सेल में मुख्तार अंसारी, उनकी पत्नी, बेटे और गुर्गे शकील के नाम से दर्ज संपत्तियों की रिपोर्ट खंगाली गई।

मुख्तार अंसारी से जुड़ी संपत्तियों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पिछले दिनों कार्रवाई की थी। हजरतगंज में अवैध रूप से बने एक अपार्टमेंट गिराने के साथ कई संपत्तियों पर बुलडोजर चला। अब ईडी की ओर से मुख्तार अंसारी से जुड़ी संपत्तियों

को लेकर पूरी रिपोर्ट मांगी गयी है। ईडी ने आवास विकास परिषद के अलावा कई विभागों को भी पत्र भेजा है। प्राधिकरण के मानचित्र और रजिस्ट्री सेल में मुख्तार अंसारी की संपत्तियों की रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही प्राधिकरण के अधिकारी ईडी को सौंपेंगे। प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ईडी की ओर से पत्र मिलने के बाद मुख्तार से जुड़ी संपत्तियां खंगाली जा रही हैं। सभी जोन के अवर अभियंताओं को भी लगाया गया है, जिससे मुख्तार से जुड़ी बेनामी संपत्तियों का पता लगाया जा सके।

बस पलटने से आधा दर्जन मजदूर घायल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मेरठ। मेरठ के सरधना में थाना क्षेत्र के नानू में मेरठ-करनाल हाईवे पर बुधवार देर रात कामगारों से भरी निजी बस पलट गई जिसमें आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया। वहां से तीन को मेरठ रेफर कर दिया। बाद में अन्य बस का इंतजाम करके कामगारों को गतंव्य के लिए भेजा गया।

» जालंधर से बहराइच जा रहे थे कामगार

घायलों के अनुसार बुधवार शाम करीब चार बजे पंजाब के जालंधर से बहराइच के लिए निजी बस यूपी 31 टी 7227 चली थी जिसमें दर्जनभर से अधिक मजदूर सवार थे। जब वह देर रात सरधना थाना क्षेत्र के मेरठ-करनाल हाईवे पर पहुंचे। इसी दौरान बस पलट गई। पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया। जहां, चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हे मेरठ रेफर कर दिया। इस दौरान विनोद, सर्वेश, लल्लू, खुरदेश, रंगीलाल और राधेश्याम घायल हो गए। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

तो देश में चल रही बुलडोजर संस्कृति!

» 4पीएम की परिचर्चा में प्रबुद्धजनों ने किया मंथन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। देश के कई राज्यों में किसी घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई का ट्रेंड शुरू हुआ है। उसकी झलक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिली। यहां जहांगीरपुरी में एमसीडी ने अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सवाल यह है कि क्या देश में बुलडोजर की एक नई संस्कृति उत्पन्न हो गई है। इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार अनिल रॉयल, सुशील दुबे, अरूणा सिंह, उमाशंकर दुबे, आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी, डॉ. लक्ष्मण यादव और 4पीएम के संपादक संजय शर्मा ने एक लंबी बातचीत की।

डॉ. लक्ष्मण यादव ने कहा, दिल्ली

परिचर्चा

रोज शाम को छह बजे देखिए 4PM News Network पर एक ज्वलंत विषय पर चर्चा

में चारों ओर अवैध कब्जा है। 40 फीसदी हिस्से में कार पार्किंग की जाती है। सवाल यह है कि न्याय की बाते कहां है। सुशील दुबे ने कहा पहली बार इस देश में हुआ था जब पांच जजों ने पीसी की थी,ये शुरूआत वहीं से हुई थी। मऊ दंगे पर योगी के दौरे के बाद बुलडोजर क्रांति उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में क्रांति ले लेगी। तो आज बुलडोजर ने नई संस्कृति पैदा कर दी है।

एसआर दारापुरी ने कहा अभी जो भी कार्रवाई हो रही, वह अमित शाह के आदेशानुसार हो रही है। ये परिस्थितियां ठीक नहीं है। कानून ध्वस्त हो गया है। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

अनिल रॉयल ने कहा, यूपी में बुलडोजर हिट हुआ तो दिल्ली ने भी वहीं राह अपना ली। बुलडोजर अगर न्याय के लिए चल रहा तो सब जगह चलना चाहिए। कानून से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि ये जो भाजपा है वह न हिंदू की है न मुसलमान की है। रही बात बुलडोजर की तो बुलडोजर की राजनीति यूपी से शुरू हुई, जो लॉ एंड आर्डर भी फॉलो नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी धज्जियां भी उड़ी। अरूणा सिंह और उमाशंकर दुबे भी परिचर्चा में शामिल हुए।

बुलडोजर पर देशव्यापी स्टे नहीं लगा सकते : सुप्रीम कोर्ट

» जहांगीरपुरी मामले में निगम की कार्रवाई पर रोक बरकरार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ उत्तरी दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई के मामले में आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल की मांग पर कोर्ट ने साफ कर दिया कि देशभर में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। हालांकि कोर्ट ने जहांगीरपुरी में निगम की कार्रवाई पर रोक को बरकरार रखा है। इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अतिक्रमण को मुद्दा बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि देशभर में इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगे। इस पर सुप्रीम

सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा : याचिकाकर्ता

जहांगीरपुरी पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने कहा यह राष्ट्रीय महत्व का मसला है। पहले कभी दंगे के बाद इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। खासकर एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। वकील दुष्यंत दवे ने दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। दवे ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में कहा है कि बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि यह मुद्दा नहीं है।

शीर्ष अदालत ने राज्यों और केंद्र से मांगा जवाब

शीर्ष अदालत ने देशभर में तोड़फोड़ के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से भी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है कि उन्हें नोटिस मिला या नहीं। इस मामले में दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा हम देशभर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। सिब्बल ने कहा, मेरा मतलब है कि इस तरह से बुलडोजर के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तोड़फोड़ तो हमेशा बुलडोजर से ही होती है. वैसे हम आपकी बात समझ गए। इस पर सिब्बल ने कहा, मेरा मतलब है कि इस तरह की कार्रवाई से पहले नोटिस जारी करना चाहिए कि आप अतिक्रमण हटा लें या हम हटाएंगे। एमसीडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने कहा दिल्ली में 1731 अनधिकृत कॉलोनी है। लगभग 50 लाख लोग रहते हैं लेकिन एक ही कॉलोनी को निशाना बनाया जा रहा है। आपने घरों को बर्बाद किया। आपने गरीबों को टारगेट किया। आपको साउथ दिल्ली या पॉश कॉलोनियों में कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा हम जहांगीरपुरी से अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, ताकि रोड साफ हों। यह अभियान जनवरी में शुरू किया गया था। इसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च में कार्रवाई की। 19 अप्रैल को अगली बार कार्रवाई होनी थी। वे अतिक्रमण और कचरा साफ कर रहे थे। यह सब तब हुआ, जब संगठनों ने इसमें दखल देना शुरू किया।

सुब्रत राय को गिरफ्तार करने लखनऊ पहुंची मध्य प्रदेश की पुलिस, सर्च आपरेशन जारी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की टीम आज लखनऊ पहुंची है। दतिया पुलिस आज सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट से जारी एनबीडब्ल्यू के साथ आई है। आरोप है कि सहारा प्रमुख और अन्य ने निवेशकों के करोड़ों रुपये हड़पे हैं जिसके संबंध में एमपी के दतिया थाने में कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं।

एमपी पुलिस सबसे पहले गोमतीनगर थाने पहुंची और स्थानीय पुलिस से सहयोग मांगा। इसके बाद स्थानीय पुलिस को लेकर सहारा शहर पहुंची और सर्च आपरेशन शुरू किया। दतिया थाने के इंस्पेक्टर रविंद्र शर्मा के मुताबिक, सहारा समूह के प्रमुख समेत आठ लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। दो हजार से ज्यादा निवेशकों के करोड़ों रुपये सहारा फाइनेंस कंपनी ने हड़प लिए हैं। निवेशकों को उनकी रकम वापस नहीं की गई। मध्य प्रदेश पुलिस का सर्च आपरेशन सहारा शहर में अभी जारी है।

डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा

अधिकारी निकलें फील्ड में, जनता से करें संवाद

» कार्यालय से निकलकर जनता के बीच जाने के दिए निर्देश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। ग्रामीण क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने अफसरों को कार्यालय से निकलकर जनता के बीच जाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने ग्रामीण इलाकों में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। डीएम ने कहा कि अगले कुछ दिनों में गुड फ्राइडे, अलविदा की नमाज, ईद उल फितर, बुद्धपूर्णिमा, बड़ा मंगल, महावीरजी का मेला सहित कई पर्व हैं, जिसमें पूरी तरह से सतर्क रहना है।

डीएम ने कहा कि पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले स्थलों पर पीस कमेटी की बैठक कर ली जाए। क्षेत्र में नियमित रूप से फुट पेट्रोलिंग करना सुनिश्चित किया जाए। भ्रमण के दौरान विभिन्न संगठनों, व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों को विश्वास में लाते हुए शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए अपील की जाए। अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों हिस्ट्रीशीटर, जिला बदर हुए व्यक्तियों एवं गैंगस्टर एक्ट के तहत चिन्हित अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखी जाए। सभी थाना प्रभारी चौकी इंचार्ज को निर्देशित किया जाता है कि स्थानीय स्तर पर भूमि विवाद अथवा अन्य समस्याओं पर त्वरित संज्ञान लेकर उनका अभिलेखीकरण किया जाए। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि थाना स्तर पर तीन

हर शुक्रवार को महिला समस्या निराकरण दिवस

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि अब हर शुक्रवार को महिला समस्या निराकरण दिवस मनाया जाएगा। महिलाओं की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण शासन की प्राथमिकताओं में से एक है। इसे देखते हुए कार्यालयों में यह दिवस मनाया जाएगा। इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इस निराकरण दिवस का समय सुबह 11 बजे से एक बजे तक रहेगा। इसमें जन शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापरक निस्तारण होगा।

माह पूर्व की विवेचना किस स्तर पर लंबित है, इसका विवेचना अधिकारी व थानाध्यक्ष क्षेत्र अधिकारी वार विवरण 3 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त किन केंद्रों में कितने गोवंश वर्तमान में है, उनके प्रवास, चारे भूसे, पीने का पानी की समुचित व्यवस्था है या नहीं नियमित रूप से चेकिंग कराने की व्यवस्था क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों के माध्यम से कराई जाए। सभी उप जिला अधिकारी एवं क्षेत्र अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे उनके क्षेत्र में गोवंश, अवैध पशु कटान एवं पशु चोरी की घटनाएं तो नहीं हो रही है।

बुलडोजर भाजपा की गैरकानूनी ताकत : अखिलेश

» विरोधियों के निर्माण को अवैध घोषित कर बुलडोजर चलवा रहे भाजपाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपाई गैरकानूनी तरीके से अपने विरोधियों के निर्माण को अवैध घोषित कर बुलडोजर चलवा रहे हैं। अब जनता भाजपाइयों के घरों, कार्यालयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण की वैधता की जांच का आंदोलन छेड़ेगी और सच सबके सामने लाएगी।

अखिलेश यादव ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण तोड़े जाने के बाद का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि भाजपा ने बुलडोजर को अपनी गैरकानूनी ताकत दिखाने का प्रतीक बना लिया है। मुसलमान व अन्य अल्पसंख्यक, पिछड़े व दलित इनके निशाने पर हैं। अब तो इनके उन्माद का शिकार हिंदू भी हो रहे हैं। भाजपा दरअसल संविधान पर ही ये बुलडोजर चला

रही है। भाजपा बुलडोजर को ही अपना प्रतीक चिन्ह बना ले। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री का जीरो टालरेंस एक बड़े जीरो में बदल कर रह गया है। माफिया, पुलिस और शासन की मिलीभगत से समस्त न्यायिक और संवैधानिक मर्यादाएं टूट कर छिन्न भिन्न हो रही हैं। लोगों में दहशत है। प्रदेश में भय और असुरक्षा का वातावरण है। अखिलेश ने कहा कि बेटियों के रात 12 बजे भी गहने पहनकर सुरक्षित बाहर निकलने का दावा करने वाले सत्ताधीशों के राज में बेटियों का जीना दुश्वार हो गया है। मेरठ में घर से बाहर तक मनचले बहन बेटियों, महिलाओं को परेशान करते रहे, मुख्यमंत्री का एंटी रोमियो स्क्वाड कहीं दिखाई नहीं पड़ा। गोमतीनगर लखनऊ में भाई के सामने बहन से छेड़छाड़ की गई। वाराणसी में 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। फूलपुर प्रयागराज में ठोकरी गांव में दादी-पोते की हत्या कर दी गई। सपा मुखिया ने कहा भाजपा दरअसल संविधान पर ही ये बुलडोजर चला रही है।

फोटो : 4पीएम

शहादत को किया गया याद

लखनऊ। शिया समुदाय के पहले इमाम व मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली की शहादत के मौके पर आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुबह की नमाज के बाद जुलूस निकालते हुए हजरत अली की शहादत को याद किया गया। इस जुलूस में भारी संख्या में शिया समुदाय के लोग शामिल हुए। प्रशासन ने मौके की गंभीरता को समझते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक **बबिता चतुर्वेदी** के लिए **4पीएम** आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (यूपी) से मुद्रित एवं प्रकाशित। **प्रधान संपादक**- अर्चना दयाल, **संपादक** - संजय शर्मा, **स्थानीय संपादक** - सूर्यकांत त्रिपाठी*, **विधि सलाहकार**: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, **वित्तीय सलाहकार**: संदीप बंसल, **कार्टूनिस्ट**: हसन जैदी, **दूरभाष**: 0522- 4078371 | **Email**: daily4pm@gmail.com | **website**: www.4pm.co.in | **RNI-UPHIN/2015/62233** डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।